नमामि गंगे परियोजना(Namami Gange Project)

गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। इस नदी को भारतवासी सबसे पवित्र मानते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2,525 किलोमीटर है। गंगा उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है।

गंगा नदी को पर्यावरण मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रदूषित और खतरे में वाली नदी घोषित किया था। गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण योजना नमामि गंगे परियोजना बनाई गई थी।

नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से मई 2014 में संसद के लिए निर्वाचित हुए तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, 'मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है।'

नमामि गंगे परियोजना को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था।

नमामि गंगे परियोजना

गंगा नदी का न सिर्फ़ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, "अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40 फीसदी आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अतः गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है"।

इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 'नमामि गंगे' नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को चार गुना करते हुए पर 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दी थी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया। योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन,नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

नमामि गंगे परियोजना: लक्ष्य

नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। युवाओं और जनता की भागीदारी के माध्यम से एक गंगा नदी के प्रदूषण और संरक्षण की दिशा में योगदान देना और दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता (सब का साथ सबका विकास) को बढ़ावा देना है।

नमामि गंगे परियोजना: उद्देश्य

नमामि गंगे परियोजना के तहत परिकल्पित गतिविधियों को आयोजित करने के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित और अत्यधिक प्रेरित करना।

समर्थन, मार्गदर्शन, पारदर्शिता, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए परियोजना के विभिन्न स्तरों पर एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना।

गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने और इसके संरक्षण के उपायों के संबंध में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों के समर्थन को सक्रिय करना और जुटाना।

प्रदूषित गंगा के परिणामों और प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और लक्षित दर्शकों को शिक्षित करना।

स्वच्छ गंगा के लिए शौचालय निर्माण, जल संचयन, संरक्षण आदि से संबंधित मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।